



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 104-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 1, 2021 (ASADHA 10, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 1 जुलाई, 2021

संख्या 37/जी०एस०टी०-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अधीन स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, मास जून, 2021 से, **प्ररूप जीएसटीआर-7** में नियत तिथि तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जोकि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करते हैं:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन कुल देय विलंब फीस की राशि को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, मास जून, 2021 से, नियत तिथि तक **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है का अधित्यक्त किया जाता है ।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 1st July, 2021

No. 37/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.